



Neutral Citation No. – 2026:AHC:175569

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-29217 वर्ष 2026

रामानंद यादव

.....आवेदकगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षीगण

आवेदकगण के अधिवक्ता:

अखिलेश कुमार खरे

विपक्षीगण के अधिवक्ता:

शा.अधि.

न्यायालय संख्या-66

माननीय न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल

1. श्री विकास तिवारी, अधिवक्ता ने प्रथम सूचनादाता की ओर से अपना वकालतनामा दाखिल किया है, जिसे अभिलेख पर लिया जाता है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



2. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अखिलेश कुमार खरे, प्रथम सूचनादाता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री विकास तिवारी तथा राज्य की ओर से विद्वान अ.शा.अधि. श्री आनंद प्रताप सिंह को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
3. वर्तमान जमानत प्रार्थना पत्र, मुकदमा अपराध संख्या-154 सन् 2026, धारा 85, 80(2), 352 भा.न्या.सं. तथा धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, थाना नवाबाद, जनपद-झांसी में विचारण की अवधि में आवेदक को जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक मृतका का ससुर है, जिसने घरेलू मुद्दों पर एक मामूली विवाद के बाद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आवेदक को केवल मृतका का ससुर होने के कारण झूठा फंसाया गया है, यद्यपि उसके विरुद्ध यह दर्शाने हेतु पर्याप्त सामग्री नहीं है कि उसने मृत्यु से पहले दहेज की मांग पूरी न होने पर मृतका को उत्पीड़ित किया। आवेदक को अन्य परिवार के सदस्यों के साथ सामान्य तथा अस्पष्ट आरोप लगाकर झूठा फंसाया गया है। आगे यह भी कहा गया है कि विवाह के 7 वर्षों के भीतर असामान्य परिस्थितियों में मृत्यु के मामले में दहेज मृत्यु की उपधारणा लागू करने हेतु, यह दर्शाने हेतु पर्याप्त सामग्री होनी चाहिए कि मृतका को मृत्यु से ठीक पहले क्रूरता का शिकार बनाया गया था, परंतु ऐसी कोई सामग्री नहीं है। अंत में यह भी कहा गया है कि पुलिस द्वारा आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है, इसलिए, हिरासती पूछताछ की कोई आवश्यकता नहीं है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह 30.03.2026 से जेल में है। यदि उसे जमानत दी जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



5. दूसरी ओर, राज्य की ओर से विद्वान अ.शा.अधि. ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया, परंतु वे उपर्युक्त तथ्य से इनकार नहीं कर सके।
6. मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के कथनों को ध्यान में रखते हुए तथा अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त (ससुर) की संलिप्तता को ध्यान में रखते हुए तथा अतिभारित जेलों तथा विचारण न्यायालयों के समक्ष आपराधिक मामलों के भारी लंबित होने को ध्यान में रखते हुए तथा साथ ही कपिल वधावन बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो, 2025 SCC OnLine SC 3038 में उच्चतम न्यायालय के निर्णय तथा माया तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2024 SCC OnLine All 6765 में इस न्यायालय के जमानत प्रदान करने संबंधी दिशानिर्देश को ध्यान में रखते हुए तथा मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरा विचार है कि आवेदक जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी है। तदनुसार, वर्तमान प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।
7. उपर्युक्त अपराध में लिप्त आवेदक-रामानंद यादव को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार एक व्यक्तिगत बॉन्ड तथा उतनी ही राशि के दो प्रतिभूतियां प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-
- आवेदक मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट करने से हतोत्साहित किया जा सके या साक्ष्य से छेड़छाड़ की जा सके।
 - आवेदक बिना किसी स्थगन की मांग किए ईमानदारी से विचारण/अन्वेषण में सहयोग करेगा।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



- iii. आवेदक जमानत पर रिहा होने के बाद किसी भी आपराधिक गतिविधि या किसी अपराध के कमीशन में लिप्त नहीं होगा।
- iv. आवेदक उसके द्वारा निष्पादित बॉन्ड की शर्तों के अनुसार उपस्थित होगा।
8. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, यह जमानत निरस्त करने का आधार होगा।
9. आवेदक तथा प्रतिभूतियों की पहचान, स्थिति तथा निवास प्रमाण को बॉन्ड स्वीकार किए जाने से पूर्व संबंधित न्यायालय द्वारा सत्यापित किया जाए।
10. आवेदक तथा प्रतिभूतियों के मोबाइल नंबर तथा आधार कार्ड का सत्यापन भी संबंधित न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए।
11. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड की गई इस आदेश की प्रति के आधार पर तथा संबंधित अधिवक्ता द्वारा इस वचन के साथ सत्यापित किए जाने पर रिहा किया जाएगा कि प्रमाणित प्रति 15 दिनों के भीतर दाखिल की जाएगी।
12. यह निर्देशित किया जाता है कि विचारण न्यायालय आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने हेतु जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली (बीओएमएस) के माध्यम से रिहाई आदेश संबंधित जेल को भेजेगा।
13. कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वह इस आदेश की प्रति आवेदक को **संबंधित जेल अधीक्षक** के माध्यम से ई-मेल या ई-प्रिजन पोर्टल के माध्यम से तथा विचारण न्यायालय को ई-मोड के माध्यम से 24 घंटों के भीतर, उच्चतम न्यायालय के **पॉलिसी स्ट्रैटेजी फॉर ग्रांट ऑफ बेल, इन रे: स्वतः प्रेरित रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 4 सन् 2021, दिनांक 31.01.2023 को निर्णीत, (2024) 10 SCC 685** तथा पिला

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



पहान उर्फ पीला पहान तथा अन्य बनाम झारखंड राज्य तथा अन्य, रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 169

सन् 2025, दिनांक 29.05.2026 को निर्णीत, के आदेशों के अनुपालन में भेजे।

14. यदि कोई प्रार्थना पत्र हो, तो उसका निस्तारण किया जाता है।

(न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल)

19 अगस्त, 2026

ए.के.आर.

Translated Version. Not For Legal Use.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”